**पत्र सूचना शाखा**
**सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0**

**राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मेलन में राज्यपाल ने विचार रखे**
**निजी एवं सम विश्वविद्यालय तथा स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु नियामक संस्था का गठन हो-राज्यपाल**
**भातखण्डे को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए-श्री नाईक**
**अन्तर्राज्यीय हवाई किराए के लिए नीति निर्धारित हो-राज्यपाल**

लखनऊः 14 अक्टूबर, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपालों के वार्षिक सम्मेलन में कहा है कि ऐसी नियामक संस्था का गठन किया जाए जो निजी विश्वविद्यालयों एवं सम विश्वविद्यालयों के कार्यों की समीक्षा करने के साथ-साथ स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में शिक्षकों के नियुक्ति एवं सुविधाओं में बढ़ोत्तरी पर भी सुझाव दें। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 80 शैक्षणिक संस्थाएं हैं जिनमें 29 राज्य विश्वविद्यालय, 25 निजी विश्वविद्यालय, 8 सम विश्वविद्यालय, 5 केन्द्रीय विश्वविद्यालय और 13 केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विशेषकर युवा आबादी को देखते हुए उच्च शिक्षा के विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

राज्यपाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भातखण्डे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय, लखनऊ को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना चाहिए। भातखण्डे संगीत संस्थान की स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी जिसके 90 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। शास्त्रीय संगीत में बढ़ती रूचि को देखते हुए वर्ष 2000 में इसे सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। यह संस्थान देश का एकमेव संगीत विश्वविद्यालय है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने से भातखण्डे संगीत संस्थान में अच्छे शिक्षकों का रूझान बढ़ेगा तथा विद्यार्थियों के रूप में देश को नवांकुर कलाकार भी मिलेंगे।

श्री नाईक ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नई नागरिक उड्डयन नीति बनाई गई है जिसके तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने का प्राविधान है। अंतरजनपदीय हवाई सेवा के लिए छोटे वायुयान की आवश्यकता होगी। केन्द्र सरकार छोटे वायुयान उपलब्ध कराने में सहयोग दे। उन्होंने कहा कि हवाई मार्ग किराए के लिए भी नीति बननी चाहिए क्योंकि एक ही समय में एक शहर से दूसरे शहर का किराया सीट की उपलब्धता के आधार पर घटता-बढ़ता है जिससे यात्रियों को असुविधा होती है।

राज्यपाल ने बताया कि जापानी बुखार से ग्रसित उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में बीमारी को रोकने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक एम0ओ0यू0 हुआ है जिसमें गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोला जाएगा जो जेई और एई प्रभावित जिलों पर अनुसंधान करके उनके निराकरण हेतु उचित प्रबंधन करेगा। लगभग दो दशक से गोरखपुर एवं उसके करीब के अन्य जिले इन बीमारियों का दंश झेल रहे हैं जिसमें निर्धन वर्ग के बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। विशेष शिविर के माध्यम से 92 लाख बच्चों का टीकाकरण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर 'न्यू इण्डिया' का प्रस्ताव स्वागत योग्य है।

श्री नाईक ने कहा कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों का सम्मेलन 6 जुलाई, 2017 को आयोजित किया गया था तथा समय-समय पर राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग व कुलाधिपति कार्यालय द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जाते रहे हैं। कुलपति सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि प्रशासनिक एवं शिक्षण व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त करने के लिए विश्वविद्यालयों में कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक एवं शिक्षकों के रिक्त पद प्राथमिकता के आधार पर भरे जाएंगे। निर्णय पर राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2016-17 हेतु सभी विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त समारोह भारतीय वेशभूषा के साथ दिसम्बर 2017 तक सम्पन्न हो जाएंगे।

राज्यपाल ने राजभवन द्वारा अन्य क्षेत्रों में किए गए नए प्रयोगों जैसे पारदर्शिता और जवाबदेही के दृष्टिगत राज्यपाल के रूप में अपनी वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन, स्वच्छता अभियान, योग दिवस का पूर्वाभ्यास कार्यक्रम, सर्वाधिक मतदान वाले बूथों का राजभवन में सम्मान, पद्म अलंकरण से सम्मानित प्रदेश के निवासियों का राजभवन में विशेष सम्मान, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस का आयोजन तथा उनकी सलाह पर उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को भव्य आयोजन किए जाने पर सहमति, राजभवन कर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आई0आई0एम0 लखनऊ में प्रशिक्षण कार्यक्रम जो संभवतः पहली बार किसी राजभवन द्वारा कराया गया, कार्यालय में कार्यनिष्पादन हेतु बेहतर सुविधाएं, राजभवन में आर्गेनिक वेस्ट कनर्वटर की स्थापना आदि के विषय पर भी चर्चा की। राज्यपाल ने

बताया कि राजभवन में फ्रैंकिंग मशीन का प्रयोग जिससे कागज की बचत हो, राजभवन में बिजली बचाने की दृष्टि से अर्थ-आॅवर का आयोजन, सोलर पावर का प्रयोग तथा एल0ई0डी0 बल्ब आदि का उपयोग कर पर्यावरण हितैषी कार्य भी किए जा रहे हंै।

राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास, ई-गवर्नेंस, ई-टैंडरिंग, पर्यटन विकास, मेट्रो रेल संचालन, अद्र्वकुम्भ मेला 2018 व यातायात विषय पर भी अपने विचार रखे।

---

अंजुम/ललित/राजभवन (397/17)